some farmer-friendly pesticides. Our country is not only able to manufacture quality pesticides, but also, export it all over the world. The environment NGOs are spending money, and even indulging in corrupt practices, so that good farmer-friendly pesticides manufactured by Indian companies are banned.

Sir, there appears to be a planned move by the European Union to phase out farmer-friendly Indian pesticides with the help of Indian NGOs. I would like to draw the attention of the Government to this through you, Sir, and request that inquiries be conducted immediately with special reference to the funding received by environmental activist organizations in our country during the last five years from countries of the European Union and to check whether these funds are being used for promoting European business and trade interests in the field of pesticides. The Government may also look into the matter and see to it that the organisations involved in environmental activities do not work against generic pesticides manufactured and exported from our country. The Government should also take effective measures to protect Indian generic pesticides industry against European pesticides.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI VIKRAM VERMA (Madhya Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

GOVERNMENT BILLS

The Civil Defence (Amendment) Bill, 2009

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPALLY RAMACHANDRAN): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Civil Defence Act, 1968, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, it is strongly felt that the civil defence can play a vital role in disaster management also. Therefore, it has been proposed to extend the role of civil defence by amending the definition of 'Civil Defence' as contained in clause 'a' of section 2 of the Civil Defence Act, 1968, so as to bring, within its purview, the measures which may be taken for the purpose of disaster management during, at, before or after any disaster.

Sir, this Bill seeks to achieve this objective.

The question was proposed.

श्री अनिल माधव दवे (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का बिल टेबल पर लाया गया है। जिस प्रकार के बिल मध्य प्रदेश और गुजरात से लौटा दिए गए थे, उससे कभी-कभी लगता था कि क्या हम आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? यह बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार का बिल आया है, लेकिन यह बिल तब तक सफल नहीं हो सकता है, जब तक कि इसके अंदर प्राण नहीं फूंके जाएंगे। मैं आर्टिकल 51(a) के (d) भाग के तहत कहता हूं कि इस देश के

नागरिकों के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के अंदर जब देश को आवश्यकता है कि उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। वे प्रयत्न केवल आपातकालीन परिस्थितियों के लिए नहीं हैं, वे 365 दिन के प्रयत्न हैं और वे प्रयत्न प्रशिक्षित होने चाहिए। हम एक रिस्पॉंसेस सिविल डिफेंस चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे पास रिस्पॉंसेस सिविल डिफेंस है? क्या हम यह खड़ा कर सकते हैं? उपसभापति महोदय, सेना में कितने मुसलमान हैं, अगर हम इसकी गिनती करके इस देश के नागरिकों से यह कहें कि आप देश की सुरक्षा में लग जाइए, तो यह ठीक दिशा नहीं है। हमें कहीं न कहीं अपने काम करने और सोचने की दिशा में एक साम्यता लानी पड़ेगी, क्योंकि देश हमारी ओर देखता है, हम देखते हैं, हम लोगों से पूछते हैं। क्या हम किसी डॉक्टर से ऑपरेशन करते समय पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के प्रयत्न होते हैं, जिन प्रयत्नों के अंदर हम शासकीय संस्थाओं के अंदर, सेना के अंदर इस बात का प्रयत्न लगाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम सिविल डिफेंस के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, मैं पहली बार बोल रहा हूं, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**... अगली बार से आप जितना चाहेंगे, मैं उतनी चर्चा करूंगा। आप पहली बार सुन लीजिए, अगली बार से मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं।

उपसभापति महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कोपेनहेगेन में हुआ है, वैसा ही यहां पर भी हो रहा है। वहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, बड़े लोग और Developed Nations agenda set करते हैं और उसके ऊपर बाकी सब लोग बात करते हैं। उन्होंने वहां एक agenda set किया कि carbon trading करेंगे। यह carbon trading क्या होती है? क्या पाप की trading हो सकती है, क्या sin की trading हो सकती है? क्या हम यह कह सकते हैं कि मैं पाप करूंगा, आप पुण्य करिए, मैं आपके पुण्य खरीद लूंगा, उससे मेरे पाप adjust हो जाएंगे? मैं कार्बन उत्सर्जन करूंगा, आप ऑक्सीजन करिए, मैं उसे carbon trading के नाम से खरीद लूंगा। उपसभापति महोदय, Developed Nations के द्वारा set किए जाने वाले trend और syllabus से बाहर आकर सोचने के लिए एक प्रभुतासम्पन्न राष्ट्र के प्रतिनिधियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके set किए हुए एजेंडे में बात न करें। ठीक वैसे ही यहां पर भी वही चीज हो रही है। यहां हम agenda set कर रहे हैं। इस देश का कोई जिला ऐसा नहीं है, जो आईएसआई की मार और पहुंच से बाहर हो, इस देश के विकास खण्ड का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, जहां लश्कर या अन्य आतंकवादी संगठन पहुंचे न हों और इस देश का कोई उपविकास खण्ड ऐसा नहीं है, जहां sleeper cells नहीं हैं। हमें इस देश के नागरिकों को आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा करना है। उन्हें प्रशिक्षित करना है, उसके लिए तैयार करना है और यह राष्ट्रीय चरित्र के बगैर नहीं हो सकता। मैं आपके सामने राष्ट्रीय चरित्र का बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं। 9/11 को WTC गिरा। देश के एक व्यक्ति ने भी खड़े होकर यह नहीं कहा कि देश का राष्ट्रपति अयोग्य है और उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने, हममें से नहीं, पूरी दुनिया में किसी ने सड़ी हुई लाश नहीं देखी, बिलखती हुई माँ से यह नहीं पूछा कि आपकी बेटी इसके नीचे दबी हुई है, बताइए कब निकलेगी और वह कह रही हो कि मेरी बेटी दब गई है। इस राष्ट्र ने, इस देश ने, इस विश्व ने ऐसा कोई चित्र नहीं देखा। यह national character है। हमारे यहां मुम्बई के हमले में क्या हो रहा था? मुम्बई के हमले के समय हम पूरी दुनिया को बता रहे थे। मुम्बई के लोग वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जब कारगिल के अन्दर हम लड़ाई लड़ रहे थे, तब इस देश के, इस समय वे सदन में उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप देश के प्रधान

मंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे ! मनमोहन सिंह जी आतंकवादियों से मुम्बई में लड़ें या इस्तीफे का कागज लेकर ढूंढते फिरें कि मैं इस्तीफा कैसे दूंगा! देश के प्रधान मंत्री से, जब वे आतंकवाद से लड़ रहे थे, हम उनसे इस्तीफा मांग रहे थे। कारगिल के समय में यह हुआ था। यह राष्ट्रीय चरित्र के विपरीत जाने वाली चीज है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपने देश के अन्दर बहुत कुछ सकारात्मक नहीं हो रहा है। बहुत सारे एनजीओ सेक्टर्स के लोग हैं, जो देश के अन्दर देश की सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहा हैं। चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, इसलिए मैं इसे बता सकता हूं। जब श्रीनगर के अन्दर पाकिस्तान के घुसपैठिए घुस आए थे, अगर उस समय रात भर जग कर एयरपोर्ट बनाने का काम किया था, तो इस देश के नागरिकों ने ही किया था। आप उन्हें स्वयंसेवक बाद में कहिएगा। जब चरखी दादरी में दो प्लेन टकरा जाते हैं, तो रातों रात उठाने वाला व्यक्ति सामने वाले का धर्म नहीं पूछ रह है, उसकी सेवा कर रहा है। जब गुजरात में भूकम्प आता है, जब तमिलनाडु के अन्दर सुनामी आती है, जब आन्ध्र प्रदेश के अन्दर बाढ़ आती है, तो ऐसे सारे कामों के अन्दर हजारों-लाखों संस्थाएं हैं, लोग हैं, वे काम कर रहे हैं।

उपसभापति महोदय, अपनी बात को खत्म करने के पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह बिल लाने से नहीं होगा, इसके अन्दर प्राण फूंकने पड़ेंगे। जैसा द्वितीय विश्व युद्ध के अन्दर लेनिनग्राड में हुआ कि जिन तस्वीरों को उतार दिया गया, जिन बातों को मिटा दिया गया, लेनिनग्राड में लड़ती हुई सेना के कहा गया कि यह वह महान पुरुष है, ये तुम्हारे पूर्वज हैं, ये दो सौ साल पहले हुए थे, ये तीन सौ साल पहले हुए थे, इनके लिए लड़ो। वे लोग लड़े। एक-एक नुक्कड़, एक-एक खिड़की, एक-एक दरवजे, एक-एक गली, एक-एक मोड़ पर लड़ाई हुई और लेनिनग्राड के अन्दर मित्र राष्ट्रों की सेना ने नाजी सेना को हरा दिया। अगर हम इस बिल के अन्दर लोगों को यह नहीं समझाएंगे कि भगत सिंह क्यों 22 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए...। सदन में बम फेंकने के बाद में यह आदमी क्यों नहीं भागा? 25 साल का चन्द्र शेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद के अन्दर क्यों लड़ता हुआ इस दुनिया से चला गया? पाकिस्तान की सेना से लड़ते हुए अब्दुल हमीद आत्मोत्सर्ग कर देता है? निर्मलजीत सिंह शेखों के बारे में आप क्या जानते हैं। जब श्रीनगर के एयरपोर्ट पर बम्बार्डमेंट हो रहा था, साइबर जेट्स हमला कर रहे थे, ऐसे समय में वह अपना छोटा से जेट ले करके टेक-ऑफ करता है और साइबर जेट को गिरा देता है। अगर आप निर्मलजीत सिंह शेखों बनने के लिए लोगों को नहीं सिखाएंगे, तो यह देश खड़ा नहीं हो पाएगा। इस देश को खड़ा करने के लिए यह जरूरी है।

उपसभापति महोदय, अंत में मैं इतनी ही बात कहता हूं कि इस देश के एक अरब, पन्द्रह करोड़ लोगों को, इस देश की सुरक्षा में सन्नद्ध करना पड़ेगा। इस देश की दो अरब, तीस लाख आंखों को देश के अन्दर आतंकवादियों को पहचानने लायक बनाना पड़ेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से स्कूली शिक्षा विभाग ने एक छोटी सी पहल की है। उन्होंने मातृभूमि रक्षा मंच बनाया है। उस मंच के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो छठी से बारहवीं तक के बच्चे हैं, वे बच्चे, महिलाएं और एनजीओज़, इन सबको साथ लिया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़े सैग्मेंट हैं। इन लोगों के अन्दर गलत को पढ़ लेने की विलक्षण क्षमता होती है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिला भी एक सैकेंड के अन्दर यह बता सकती है कि इस आदमी का इरादा ठीक नहीं है। उसकी आंखों में

ईश्वर ने वह योग्यता दी है। ऐसे ही जो तरुण युवक हैं, उन युवकों के अन्दर भी क्षमता होती है कि वे देख कर ही यह बता देते हैं कि आज जब मैं स्कूल जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक गलत टाइप का आदमी घूम रहा था।

अभी 15 दिन पहले हमारे गृह मंत्री जी इस्लामिक टैररिज्म और हिन्दु टैररिज्म की बात को ले करके सदन में इंटरवीन करते हुए कह रहे थे कि चौबीस घंटे इस व्यवस्था के साथ रहता हूं, इसलिए मैं आपका कष्ट समझ सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि जब एक व्यक्ति को दिन-भर इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी दी जाती है, तो उस व्यक्ति की नींद और चैन सब खराब हो जाता है। उसका हरदम यह लगता है कि मैं देश की सुरक्षा कैसे करूं? इसलिए मुझे लगता है कि इसके अन्दर आप एक अरब, पन्द्रह करोड़ लोगों को काम में लगा सकते हैं। इससे बड़ी देश की सेवा कोई हो नहीं सकती है। आपको केअरफुल भी बहुत रहना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से 10-15 साल पहले इस देश के एक प्रधान मंत्री ने गंगा को साफ करने के लिए एक इरादा दिया, वादा किया, पैसे दिए, लेकिन उनके साथ वालों ने उनको यह काम करने नहीं दिया और वह इस संसार से चले गए। गंगा आज भी मैली है, गंगा साफ नहीं हुई। इसलिए आप इस बिल अमेंड कर रहे हैं, इसका स्वागत है, आप करिए, लेकिन इसके अन्दर प्राण फूंकिए। इसके लिए इस देश के एक अरब, पन्द्रह करोड़ लोगों को और एक-एक पंचायत को अगर आप काम में लगा लेंगे, तो मुझे लगता है कि यह बिल सार्थक होगा। पूरा समाज आपके साथ खड़ा हो जायेगा। लेकिन यह सब करने के लिए जो प्रशिक्षण की आवश्यकता है, लिट्रेचर की आवश्यकता है, वह भी पूरी करनी पड़ेगी। इसको खड़ा करते समय आप वह गलती न करें, जो भारतीय सेना के अन्दर धर्म के आधार पर गिनती करके की जा रही है। इस प्रकार की गलतियां अगर आप नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले दो-पांच या सात सालों के अन्दर यह बिल एक प्रभावी गिल के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। वन्दे मातरम् !

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to support this Bill, the Civil Defence (Amendment) Bill, 2009 which has been based on the recommendation of K.M. Singh Committee partially. Mr. Dave has made a few comments. It was his maiden speech. I really didn't want to react to his points which he had been raising but some points which he had raised do need clarification. I fully agree that there is a fear of terrorism in different parts of the country. I fully agree that this is the responsibility of every citizen in the country. But I also like to know from him what that organization which he belongs to – I am not mentioning the names – is doing in this effort. I don't want to go into those details.

Sir, he has talked of national character. The national character is the responsibility of every citizen of the country. It is not the responsibility of the Government alone, it is the responsibility of you and me and everybody else. I fully support you on that. The character of MPs, MLAs, bureaucrats, businessmen and ordinary man on the road has to improve. And how will it improve? It would improve by education. I have no problem on that. I fully support him when he says that training has to be given in the schools. Even for this purpose, training has to start in the schools. He says that they want resignation from the Prime Minister on Kargil; but is it not true that the Foreign Minister of the country had gone along with one terrorist? Was that right? He has forgotten to mention about that.

Was that a right action taken to save this country? ...*(Interruptions)*... He has mentioned, that is why I am saying this. Otherwise, I would not have mentioned this. ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) : बागड़ोदिया जी ...**(व्यवधान)**...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I heard him very carefully; I heard him very peacefully. But they cannot change their habit of interrupting. ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सर ...**(व्यवधान)**... नहीं, नहीं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही ...**(व्यवधान)**... उन्होंने दोनों चीजों का उदाहरण दिया ...**(व्यवधान)**... मुंबई का भी दिया और कारगिल का भी दिया ...**(व्यवधान)**... बागड़ोदिया जी ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has not yielded. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record.

श्री एस.एस. अहलुवालिया : *

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Ahluwalia will not change his habit of interfering.

श्री एस.एस. अहलुवालिया : *

SHRI SANTOSH BAGRODIA: You cannot cow me down. I have not allowed you to interrupt. If I have made a wrong statement, it would be deleted. ...*(Interruptions)*... Have I said anything unparliamentary? Did I interrupt him? Then, you may also peacefully listen to me. ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : *

श्री संतोष बागड़ोदिया : सुनने की तो हिम्मत है नहीं। उन्होंने गंगा प्लन के बारे में कहा। Yes, राजीव गांधी जी ने गंगा प्लान दिया। उन्होंने उसको क्लीन करवाया। लेकिन, उसके बाद उसकी सफाई नहीं की गई। ये जो प्लांस होते हैं, उन्हें आपको समझने की आवश्यकता है। अगर एक बार घर में सफाई होती है तो वह घर फिर गंदा नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। वहां पर गंदगी की हमेशा सफाई करनी पड़ती है। वह continuity maintain नहीं हुई। बीच में आप भी सरकार में आए थे। आपने continuity maintain नहीं की, इसलिए इसकी जिम्मेवारी आप की भी है। मैं यह नहीं कहता कि हमारी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हम भी जिम्मेवार हैं, लेकिन आपको भी वह continuity maintain करनी चाहिए थी, जिसे नहीं कर पाए। Anyway, coming back to the Bill, Sir. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश) : सर, ...**(व्यवधान)**... उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ...**(व्यवधान)**... उन्हेंने कुछ भी नहीं किया, मगर इन्होंने क्या किया? यह मैं जानना चाहती हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री संतोष बागड़ोदिया : हमने तो गंगा को साफ किया। उसके लिए रुपया दिया और उसकी सफाई करवाई। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप बोलिए, बोलिए।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Coming to the Bill, Sir. ...*(Interruptions)*...

---

*Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is now coming to the Bill. Please, allow him to speak.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, the Statement of Objects and Reasons states that this Bill affords protection to any person, property, place or thing in India against any hostile attack, whether trom air, land, sea, etc., and civil defence is intended to be organised timely on voluntary basis. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is speaking on the Bill. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: When we talk of voluntary basis, I would like to mention here, Sir, in the United States there are volunteers for civil defence; doctors, engineers, politicians and big businessmen, all get trained themselves for. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : आप प्लीज़ सुनिए ...**(व्यवधान)**... वह जो बोलना चाहते हैं, वही बोलेंगे। आप जो चाहते हैं, उसे वह नहीं बोलेंगे।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, they get themselves trained even at the age of 40, 50 or 60 years. They want to be trained for civil defence because they want to do something for the society. That kind of character needs to be inculcated in our society, that we must also get trained. You cannot become a fire-fighter without training. You cannot do medical service without training. I would request the hon. Minister to start that kind of training for every citizen in the country, and whoever wants to be trained voluntarily, must be trained that way. Only then voluntary service would start.

Sir, the Disaster Management Act, 2005, has been enacted. Now, there is an Act for that. I have no objection on including disaster management in this Bill. But, I will request the Government that please do not depend only on the civil defence system. Disaster management cannot be handled – it is just impossible – only by the civil defence systems because this is a much bigger problem. For example, I will straightway tell you about what happened in Jaipur. Recently, we had a fire in the oil depot in Jaipur. It is our own Government. I am not going into that, and different Governments have come at different times. But, the point I am trying to make is that the District Administration had no detailed disaster management preparedness programme. I accept this because it is not there in most parts of the country. Sir, while dealing with the recent fire in the oil depot in Jaipur, the District Administration did not have any plan. As I said, the delay in relief caused massive loss of life and property. It has now been reported that the District authorities later conjured up a district disaster plan by copying and pasting other districts' plan. If we do these kinds of activities, it is not going to help the country, or any citizen in the country. The court has now ordered the court has to interfere here also--that FIR should be lodged against people involved in it. I have mentioned this because it is very easy to say that include disaster management in this Civil Defence

Bill. But, do we have enough resources? Do we have enough volunteers to handle that kind of situation? Sir, the Committee has recommended many more things. If they are coming under the rules, I have no objection, but they should not be overlooked, like the Building Material Technology Promotion Council has classified 241 districts as multi-hazard districts. What are we doing about that? K.M. Singh Committee recommended authorisation of 800 wardens per district or 20 lakh populations. Do we have this plan of 800 wardens? Do we have resources for this? Sir, the Committee has also recommended strengthening of training institutions, involvement of Panchayati Raj institutions, revamping the structure of civil defence. Do we have plans for all this? Do we have resources for all this? Sir, the NCC, NSS, Nehru Yuva Kendras are being integrated with civil defence networks. All these things should be trained for civil defence. For all this, Rs.100 crore has been provided in the Eleventh Plan to revamp the civil defence. Sir, I request the hon. Minister to appeal to the Finance Minister, Rs.100 crore in five years is neither here nor there. Further, we want to include the disaster management also in this, and we want Rs.20 crore for a large country like this. We need much bigger amount of resources and we need much more training. We have to have a plan for that. Sir, under the scheme, the Civil Defence Institutes in 20 States, U.T.s will be strengthened, and civil defence set-ups in 100 identified districts will be strengthened.

(THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR) in the Chair)

It is in 100 identified districts only, out of probably 600 districts. How can we manage? We cannot do it in ten years. There is no question of identifying. If we want every citizen in the country to get the benefit of civil defence, we have to strengthen this system in every district, every village, every town. There is no question of identifying only 100, and then leaving other 500 districts out of the purview from this kind of service. What will happen to those districts? Sir, I request the Government to respond. The State Governments and district authorities should have a list of enlisted volunteers. Do you have the list of volunteers? Do you have a plan to have a register of volunteers? If there is any exigency, an organised response is required. How are these volunteers organised? Are they attached to any district police formation, or are there permanent district-level civil defence formations? What are we doing about strengthening this information? I would like to tell the hon. Minister that we don't have all this information readily available. Unfortunately, we do not have proper registers even for the blood groups, what to speak of this kind of much better registers.

The disasters are defined as natural or manmade. Our cities have been the targets of terror strikes; our countryside is witnessing naxal violence; certain States are witnessing even secessionist violence; and, incidents of communal and caste violence are reported in the country. Why did I mention all this? Sir, including disaster management in the civil defence is all right but we have much

bigger problems than this. I support this Bill; I will support further activities also but we need much more strengthening. That is why, I am stressing on the point that simply including the disaster management in the civil defence is not the solution; this requires much more effort than this.

The naxals are attacking the civil infrastructure or the running trains. How can the volunteers be used to provide relief to those affected in an accident or a bomb blast. He mentioned about 'Bombay'. This is true. 'Bombay' is a much bigger thing. How many people will take the risk of their lives? When there is an accident on the road, how many people are willing to help that accident victim? In France, there is a law according to which, if you find an accident victim on the road, it is obligatory on your part to help him and take him to the hospital. Do we have that kind of law? Do we have that kind of character? We are scared. If there is a trouble on the road – I have seen it with my own eyes-somebody with one pistol can control probably one thousand people. Nobody wants to come forward. We have seen women being assaulted. How many people come forward to help those women? Whatever we talk about character, it requires much stronger training, much stronger effort. I am not complaining about any individual or any organisation. Mr. Dave, I am with you. We need a complete support from every side, and, that is why, I say, character can be built only if all of us are willing to join together and try to build up the character. ...*(Interruptions)*... I do not know what he has said.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (Bihar): What about political character! ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Yes, you are right. Even our political character has to improve, and, I think, some of you have to improve more than what is required in case of some of us. This is but natural. I am not excluding the politicians. They are also part of the system. I have said that every individual in the country needs to improve upon himself. If he is good, he has to be better. Even the religious heads, even the religious leaders, everybody has to improve. ...*(Interruptions)*... I do not know but I am told that many of your friends are within. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Please do not disturb. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: You are also with the Party. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Vice-Chairman, Sir, through you, I am telling him. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Don't divert. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I am looking at you because you are looking handsome, smart and all that. But let me look around also. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Thank you. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I will not take very long time. Will the NDMA, the National Disaster Management Authority, also consider using the Territorial Army for this purpose? This is a trained Territorial Army, which is available in the country. Should we include that also in the civil defence. ...*(Interruptions)*... Sir, we must have a system by which. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, there should be some disaster management in the House also. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Rudyji, please. ...*(Interruptions)*... Don't disturb. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Yes, there should be some disaster management in the House and your cooperation is required. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Why are you responding?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I come to my last point. ...**(Time-bell rings)**... ...*(Interruptions)*...

Sir, they will not let me make my last point. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Please, please. ...*(Interruptions)*... Please. Order please. ...*(Interruptions)*...

श्री संतोष बागड़ोदिया : हमारे मित्र हैं, बात करने में अच्छा लगता है, कोई हर्ज़ नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): No, no. Don't respond. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I am not going to be disturbed. इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? ये सब लोग एक साथ बोलेंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान ने मेरी voice को top पर लाकर छोड़ दिया, फिर वह मशीन ही गायब हो गई। ...**(व्यवधान)**... अब उसको वापस कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं है। Sir, the last point I want to make is ...*(Interruptions)*...

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, लॉ पर बहस चल रही है, लेकिन इनकी पार्टी के सदस्य नहीं सुन रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Your point please. ...*(Interruptions)*... रूडी जी... ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: For this, Sir, what kind of system should be there for monitoring the performance of the district authorities? We should have a monitoring system which is available not on three months' basis or six months' basis, but we should have a monitoring system which is available on weekly basis. Then only something good can happen to the country. In today's world, when we have the computer system, I am not saying daily, at least, weekly report should come to the proper authorities so that if there is any problem in any district, it can be corrected immediately.

With these words, Sir, I would like to conclude. And, Sir, I believe, that there is no combat activity in this. This is meant for civil defence, even if it is national disaster. We are not trained for combating. That is the responsibility of the Army. With these words, I thank you for giving me this opportunity. I hope everybody in the country will support this and the day we take this responsibility, whether the ISI, whether any divisive forces, either because of religious or because of caste, nobody will be able to touch anybody in the country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Thank you.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I remember in 1947, I was in Kolkata. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल) : सर, ये फिर शुरू हो गए।

श्री संतोष बागड़ोदिया : सर, अगर मेरा टाइम पूरा हो गया है, तो मैं बोलना छोड़ दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : आप खत्म कीजिए।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I think, I am allowed and I have enough time. Still I am going to finish.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Please conclude.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, in Kolkata, my house was surrounded by all minority people in 1947. There was so much fear, so much bloodshed all around. But the people both Hindus and Muslims were there in our own area. Those who come from Kolkata or who know Kolkata, there was a Shudh Khadi Bhandar which was opened by Mahatma Gandhi, I was staying in that house only. There were Muslims just behind my house. We could talk to everybody. सबको हम चाचा, मामा, ताऊ बोलते थे। And, during that trouble also, there was hardly any bloodshed in that area because we tried to help each other. That kind of training, that kind of desire has to come in you, in me, in these people and everybody else. If we start saying that don't count either in the Army or somewhere else, or, you don't do this, don't do that on religious basis, please let things move. We have to help every community. Either due to religion or due to caste, we cannot differentiate. If some community or some people from any other religion are not developed enough, we have to have figures. We have to have information about it. What is wrong in taking the information? Sir, with this, I once again thank you for allowing me to speak on this subject. Thank you.

श्री समन पाठक (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं नागरिक सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2009 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ विषयों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। महोदय, नागरिक सुरक्षा का यह विषय भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि आम आदमी को सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ यांत्रिक रूप से, मशीनी रूप से नहीं, बल्कि आम आदमी को इसमें involve करा कर, विभिन्न सरकारी

एजेंसियों, गैर सरकारी एजेंसियों और स्वेच्छा संस्थानों, सभी को इसमें involve कराकर इस नागरिक सुरक्षा को कैसे और मज़बूत किया जाए, इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन विधेयक के संबंध में अभी-अभी माननीय सदस्यों ने यहां पर जिक्र किया कि आतंकवाद, आतंकवादी हमला, नक्सलवाद, देश में होने वाली कोई भी घटना या प्राकृतिक प्रकोप या अन्य कोई ऐसी दुर्घटना, जो देश को नुकसान पहुंचाती हो या ऐसी मानवीय आपदाएं, जिनके कारण विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता हो, ऐसी आपदाओं से हम कैसे निपटें ताकि जान माल की हानि कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए disaster management को और अधिक शक्तिशाली और चुस्त करने की जरूरत है। महोदय, 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाने के बाद हर जिला स्तर पर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको लेकर जाना था, लेकिन आज की तारीख में स्थिति यह है कि देश के कई हिस्सों में लोग इस आपदा प्रबंधन अधिनियम का नाम तक नहीं जानते हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए केवल विधेयक लाने से ही काम नहीं चलेगा, इसके लिए एक मजबूत संकल्प की जरूरत है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे इसका सही तरह से implementation हो। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो disaster management है, इसको केवल बिल से नहीं, बल्कि infrastructure की दृष्टि से और equipments की दृष्टि से भी मज़बूत करना जरूरी है। अगर आपके पास कोई infrastructure नहीं है, आपके पास मजबूत equipments नहीं हैं तो कैसे आप इसको manage कर पाएंगे? मैंने इस विधेयक में कहीं पर ऐसा नहीं देखा कि किस तरह से आप इसको अपडेट कर रहे हैं, आप किस तरह के equipments, किस तरह का infrastructure तैयार कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, यह सब मैंने इस विधेयक में नहीं देखा। दूसरी चीज़ यह है कि कोई भी घटना हो - जैसे प्राकृतिक प्रकोप के लिए यह जरूरी है कि forecasting या पूर्वानुमान सही ढंग से हो और यह forecast साधारण आदमी तक, आम आदमी तक समय पर पहुंच सके। लेकिन दुर्भाग्यूपर्ण बात यह है कि दुर्घटना होने के बाद हम लोग उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं कि ऐसा होने वाला था, लेकिन हम लोग पहले से उसका सही तरह से पूर्वानुमान लगाकर उसकी घोषणा नहीं करते। इसी प्रकार मौसम विभाग की हालत है। हमारे देश के ग्रामीण एरिया में, मछुआरे या किसान आम तौर पर मौसम पर निर्भर रहते हैं। जो लोग मौसम की forecasting करते हैं, वे यह कह देते हैं कि कहीं-कहीं गरज के साथ छींटें पड़ने वाले हैं, लेकिन कहां-कहां पर ऐसा होने वाला है, इसके बारे में सटीक रूप से नहीं बताया जाता है। इस प्रकार का जो हमारा infrastructure है, उससे हम कैसे disaster management को मज़बूत बना सकेंगे, इसके बारे में गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। इसके लिए उच्च तकनीक की जरूरत है तथा सुरक्षा एजेंसियों और equipments को मज़बूत करना बहुत जरूरी है। इसके साथ-साथ मैं एक जरूरी बात यह कहना चाहता हूं - जैसे माननीय सदस्य ने अभी-अभी जिक्र किया कि इसके लिए जो funding system है, वह ठीक नहीं है। कोई भी आपदा आने के बाद हम सबको गुहार लगाते हैं कि इसके लिए फंड की जरूरत है। पहले से एक मजबूत funding होना बहुत जरूरी है ताकि दुर्घटना होने के बाद हम उस जगह पर तुरंत relief दे सकें, इसके लिए पहले से ही फंड्स की सही व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। साथ ही नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपदा संबंधी सुरक्षा के लिए व्यापक रूप से प्रशिक्षण जरूरी है।

12.00 NOON

आज हर नागरिक को ट्रेनिंग की जरूरत है, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान को या जो स्वैच्छिक संस्थान हैं, जो वोलियंटरिली काम करते हैं, उनको भी सही तरीके से ट्रेनिंग देने की जरूरत है, अवेयरनैस करने की जरूरत है। आज देश में ऐसी स्थिति है कि अगर कोई बच्चा खाई में गिर जाता है तो हमको इसके लिए सेना को बुलाना पड़ता है। तब जाकर ही उसको बचाया जा सकता है। तो हम हर नागरिक को इस तरह से ट्रेनिंग दें, हर एजेंसी को ट्रेनिंग करें जिससे हमें छोटी-छोटी घटनाओं के लिए सेना का इंतजार न करना पड़े कि जब सेना आएगी तभी यह काम होगा। आतंकवाद के सवाल पर या प्राकृतिक आपदा के सवाल पर हो या कोई भी छोटी-मोटी घटनाओं के ऊपर हो, इस तरह से जो केम्पेनिंग और ट्रेनिंग है, यह हर एक नागरिक तक पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था करना जरूरी है।

लास्ट में, मैं माननीय मंत्री जी का रिहेबिलिटेशन की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोई भी नेच्युरल कलैमिटी हो या आपदा हो या कोई भी ऐसी दुर्घटना के बाद रिहेबिलिटेशन का सिस्टम है, इसमें कोई भी सरकार हो या कोई भी मंत्री हों, वहां तुरंत जाकर एलान कर देते हैं कि हम लोग ये देने वाले हैं तथा बड़े-बड़े वायदे कर देते हैं, घोषणाएं कर देते हैं। लेकिन असलियत में उनकी जो रिहेबिलिटेशन की सुविधा विक्टम तक पहुंचने में बहुत देरी लगती है, कहीं-कहीं तो वह घोषणा, घोषणा ही रह जाती है। उन तक राहत नहीं पहुंचती है। इसलिए इस ओर भी बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसके साथ ही मैं यह नागरिक सुरक्षा विधेयक का स्वागत करूंगा और हर नागरिक को इससे लाभ पहुंचे, हर नागरिक को ट्रेंड करें और मैंने जो खामियां बताई हैं, मंत्री जी, जरा इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।

श्रीमती जया वच्चन : धन्यवाद, सर। महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। मुझे याद आता है कि जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी माता जी ने मुझे सिखाया था कि जब खाना खाओ, उतना ही अपनी थाली में लो जितना आप खा सकती हो या हजम कर सकती हो। वह इसलिए कहती थी कि वे जब छोटी थी तो बंगाल में अकाल पड़ा था, और वहां लोग कटोरा लेकर घर-घर जाते थे और कहते थे, मां, भात दाओ, फेन दाओ। भात दाओ मीन्स चावल दो, फेन दाओ मीन्स, चावल का पानी दो। तो वहां लोग इतने भूखे थे तथा मर रहे थे। यह जो बात थी, उसका असर मेरे दिमाग पर बहुत ज्यादा पड़ा और आज तक यह आदत मुझ में है कि मैं जितना खाना चाहती हूं उतना ही लेती हूं। यही शिक्षा मैंने अपने बच्चों को भी दी है। कहीं अगर मैं देखती हूं कि कोई खाना वेस्ट कर रहा है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कभी-कभी आप बाहर जाते हैं, होटलों में मैंने देखा कि वहां खाना आर्डर करते हैं और कुछ बच जाता है। मैं हमेशा यह कहती हूं कि इसको पैक कर दो और रास्ते में कोई गरीब मांगता होगा तो उसे दे देंगे। इस देश में कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, यह मेरी इच्छा है। पता नहीं, यह मेरे जीवनकाल में पूरा होगा या नहीं। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आज मैं यहां खड़ी हूं इस बिल को सपोर्ट करने के लिए, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हिन्दुस्तान में यही अवस्था है हर इंसान की, हर जाग्रत इंसान की यही है सोच। इतने सालों बाद भी हम इस तरह के शब्द अपने बिल में इस्तेमाल कर रहे हैं - 'a vibrant institution' 1968 का बिल हम vibrant institution बनाना चाहते हैं। इतने दिन तक वाइब्रेशन क्यों नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया? इतना मौका हम लोगों को मिला, सर, यह बहुत दुख की बात है। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : जब जागा तब सवेरा।

श्रीमती जया बच्चन : जब जागे तभी सवेरा, यही तो मार गया हम सबको। हमको जगना चाहिए था, 60 साल पहले। उस वक्त अंग्रेज आए थे, अब अमेरिकन आएंगे, लिख लीजिए। आप लोगों की पूरी तैयारी है। यह हमारी बदनसीबी है कि शायद हम हमेशा गुलामी से ही गुजरेंगे। हर फिर लड़ेंगे, उस लड़ाई में कुछ बड़े-बड़े लोग मर जाएंगे, तब फिर देश को आजादी मिलेगी। इसके बाद कुछ लोग और आ जाएंगे, देश को फिर गुलाम बनाने के लिए। जब जागे तभी सवेरा, मैं इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं करती हूं। यह गलत बात है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : आप उधर ध्यान न दें और अपनी बात कहें।

श्रीमती जया बच्चन : उन्होंने टिप्पणी की थी, इसीलिए मैंने बोला है। सर, हम डिफेंस की बात करते हैं, लेकिन जो हमारे पास मौजूदा डिफेंस है, हम उसको तो तैयार भी नहीं रख सकते हैं। हम उनको जूते नहीं दे सकते हैं। हमारे जवान बर्फ में काम करते हैं। वे वहां पर दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनको मोज़े व जूते नहीं दे सकते हैं। बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं, जिनको कहकर मैं शर्मिन्दा नहीं करना चाहती हूं। जो हमारी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, उनको तकलीफें नहीं होनी चाहिएं। अगर हम उनको ये चीजें प्रेवाइड नहीं कर सकते हैं, बेसिक नेसेसिटीज़, कम्फर्ट और लग्ज़रीज़ की बात को छोड़ ही दीजिए, तो फिर हम किस बिल की बात कर रहे हैं? हम किस को वाइब्रेंट करने की बात कर रहे हैं? मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है और मैं शर्मिन्दा भी बहुत महसूस करती हूं कि यह कुछ व्हाइटवाश किया जा रहा है। मुम्बई में एक तो डिजास्टर हो गया, आपने अभी कहा मुम्बई के लोग खड़े होकर देख रहे थे, यह गलत बात है। मुम्बई के लोग खड़े होकर देख नहीं रहे थे, बल्कि मुम्बई के लोग बाहर आए। वे हमेशा हर तकलीफ में एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। मैं यह कहती हूं कि मुम्बई की सरकार खड़ी होकर देख रही थी। यह तो होना ही नहीं चाहिए था। मुम्बई में फ्लड आया, नहीं आना चाहिए था। मुम्बई में आतंकवादी आए, वे नहीं आने चाहिए थे। Mumbai, which is the financial city of the country, financial capital of the country! Are we prepared? Were we prepared for the defence of that city? I am really confused. सर, मैं भावुक हो गई थी। मैं बुद्धिजीवी नहीं हूं, हृदयजीवी हूं, इसलिए भावुकता की बात करती हूं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : बोलिए, आप बोलिए । ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती जया बच्चन : आप लोग तो यही चाहते हैं कि शार्टकट में काम खत्म हो जाए। ...**(व्यवधान)**... आप दो घंटे तक बात कीजिए। ...**(व्यवधान)**... बिल पर ही आ रही हूं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : जया जी, आपका समय बर्बाद हो रहा है।

श्रीमती जया बच्चन : सर, अगर वे इस तरह से टोकेंगे, तो मैं समय लूंगी। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : प्लीज़, आप लोग बीच में न बोलें। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती जया बच्चन : आप मुझे मत टोकिए, मैं समय नहीं लूंगी। यदि आप टोकेंगे, तो मैं समय लूंगी। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : प्लीज़, प्लीज़। आप बोलिए

श्रीमती जया बच्चन : भुवनेश्वर कालिता जी, मकान नहीं दिया, तो ठीक है, लेकिन टिप्पणी तो मत करिए। मैं टिप्पणी करूंगी तो आपको बुरा लगेगा। आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : बोलने दीजिए, बोलने दीजिए।

श्रीमती जया बच्चन : सर, असल बात तो यह है कि जो हमारे डिफेंस के लोग हैं या जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वे किसी भी सरकारी ओहदे पर हैं, अगर हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे, तो आज के इस जमाने में, महंगाई के जमाने में, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, उनको सुविधाएं नहीं देंगे, तो डिजास्टर होते रहेंगे। Disaster of corruption of mind, heart and intention. सर, हमें इसको रोकना है। हमें इसके लिए तैयारी करनी है। हमारे देश में अमीर लोग जिंदा रह सकते हैं, मगर आम आदमी आज जिंदा रहने के काबिल नहीं है। मैं छोटी-छोटी बातें बता रही हूं कि हम किस तरह से तैयारी रखते हैं। अभी हमारे यहां दिल्ली में कॉमन वैल्थ गेम्स की तैयारी चल रही है। जिसकी वजह से मैट्रोज बन रही हैं, फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं, हर कहीं सड़कें बंद की गई हैं। There is no proper lighting up of the signboards. रात को गाड़ियां चलती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। Road breakers, speed breakers are made without properly giving any kind of guidance to the person who is on the road driving a car. There are accidents every day. उस दिन जब मैं अपने घर से यहां आ रही थी, मुझे आधा घंटा, पैंतालीस मिनट लगते हैं, सड़के इतनी खराब थीं, मुझे लगा कि स्पोन्डेलाइटिस की यह तकलीफ मुझे कॉमन वेल्थ की वजह से हो गई है। Roads are so bad. If we are preparing Metro links, if we are making flyovers, should we have not thought of giving people on the road, at last, smooth roads? Forget the traffic jams. What kind of preparedness are we talking about? मुझे याद है, उस दिन जब मंत्री जी कह रहे थे, वे बहुत सीनियर मंत्री हैं, कि मीडिया ट्रायल मत करिए, मगर सर, मीडिया ट्रायल जरूरी है। अगर मीडिया ट्रायल नहीं होगा तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। Who is going to point out these things? We bring a Bill; we discuss it; we pass the Bill without any debate! And, then, what happens? In 60 years, we have not been prepared for any kind of disaster that this country is facing every now and then. Whether it is floods, whether it is महंगाई। आप क्यों नहीं सोचते हैं कि हम इस महंगाई को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सम्भाल तो सकते हैं? इस तरह के preparedness को हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? And you are wanting to bring vibrancy! Where? I don't know! How? I don't know! I do support this Bill, but with a lot of hesitation and with a lot of guilt. And I only hope that this Bill really means what they are trying to say.

I would like to bring out certain points here. They are talking about 'against any hostile act'. I do not know what they mean by 'hostile act'. You have people in the defence, civil defence. They are so poorly paid that instead of defending people, they are extorting money! There is extortion. Is that preparedness? Okay, you are asking us to support your Bill. But what have you done in the past? What kind of defence have you given? These people you have are so poorly paid सर, उस आदमी के

पास और कोई चारा ही नहीं है। चाहे आप ट्रैफिक पुलिस को देख लीजिए, आम तौर पर आप फिल्मों में बहुत सी चीजें देखते हैं, जो देखने में अच्छी नहीं लगतीं, हम लोग पार्लियामेंट में आकर उनको क्रिटिसाइज करते हैं, सेंसर बोर्ड वाले काट देते हैं, मगर जो करप्शन की चीजें हैं, वे दिखाई जाती हैं, सच्चाई दिखाते हैं, शीशा दिखाते हैं। यह सही है। यह इसलिए है, because we have not given them proper provision; we have not looked after them in these last 60 years. I don't care whether the Government is this side or that side. Natha Singh and Prem Singh, one and the same thing! Every year, the Mumbai Police holds a charity programme for the welfare of its families. It is a shame, Sir! It is a shame that this huge Institution needs the help of charity welfare programmes for its families. It should be our primary concern to look after the people who are here to take care of us, whether it be Police or whether it be Defence Services. Nobody wants to join the Army, the Air Force and the Navy today! It is tough, Sir, because they are so poorly paid. किसकी रक्षा करेंगे? अपने परिवार की या अपने देश की? कोई जाना नहीं चाहता है। There is no future.

You have not created any national feelings among the younger generation of today. It is very sad. It is a very sad state of affairs.

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : आप conclude कीजिए प्लीज़।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: I am concluding, Sir. I realise that there is a lot to say if you start pointing out the faults. There are so many unaccountable ones. Anyway, I am supporting this Bill. My party supports this Bill with a hope that we are not going to be standing here after another 60 years and our grand-children will not be talking and discussing the same subject here. Thank you very much.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I welcome this piece of legislation which seeks to strengthen the role of Civil Defence in disaster management. I understand that this is the limited objective of this Bill. So, I confine myself to it.

Sir, the Government of the day may or may not be able to prevent a disaster. But the Government can surely ensure that the citizens and the public are well prepared to tackle a disaster once it occurs.

Sir, keeping in view the National Disaster Management Authority and its role, I would like to know from the Government whether the Civil Defence institutions will involve the panchayats and other local bodies like the municipalities to participate in disaster management. What are the plans of the Government to involve the panchayats and the municipal institutions in disaster management? There is a great scope for giving training and creating awareness in all panchayat bodies in disaster management.

Sir, we have a huge population. They can be mobilised and motivated by the Civil Defence Forces and they can be taught how to tackle and endure disasters, and also to understand what can be done. We have a number of institutions to be involved and made aware of disaster management. They must be made aware of disasters.

Sir, Civil Defence Forces can play a great role by attracting volunteers. The Civil Defence is a potent force. The Administrative Reforms Commission has recently stated that the ideal number of volunteers would be one for every thousand population. So, the Civil Defence should concentrate on raising volunteers and training them. They would be the first to face the disaster.

Sir, the Government should also clarify whether the National Disaster Management Authority would have jurisdiction over the Civil Defence or whether it would be with the Home Ministry. It should be clarified. The Government should also define the role of the National Disaster Management Authority in the management of National Disaster Response Forces, Right now the Home Ministry coordinates the Response Forces. With the strengthening of the Civil Defence, what would be the relationship among the various bodies dealing with disaster management in the country? The Government must clarify. The Government should also clarify how it will create synergy among the National Disaster Management Authority, the Home Ministry, the National Disaster Response Forces and the Civil Defence. There is always a danger of each of them pulling in different directions. It must be defined and clarified. This amendment, I understand, will enable the Government to use the Civil Defence for disaster management. That is the limited object of this Bill. Let us hope that the Government will implement such plans on a fixed time-frame. What is the time-frame? Many a time in our country, we pass laws and then we forget about them. We imagine that once a law is passed, that law has been effectively implemented. But that does not happen in India. Unless the Government sets the targets and tests the targets of the Civil Defence, this effort will not be utilised to its full potential. Here I would like to know from the Government whether it has any plans to regularise the Civil Defence workers and make them permanent as per the rules. This is important in the context of preparedness of the country to face any disaster in any given situation. I think this Bill has only this limited objective. I am not here to raise all issues concerning internal security or external security. This Bill, I understand, has a limited objective of strengthening the role of the Civil Defence in disaster management. With these observations, I welcome this Bill. Thank you.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Bill with a few observations. I only want to seek one clarification from the hon. Minister. Sir, the Civil Defence Act, 1968 applicable to the whole of India aims at providing for continued maintenance of Civil Defence services which are already in position in the States and Union Territories. It further says, "The Civil Defence is intended to be organised primarily on voluntary basis as an integral part of the defence of the country on a limited scale. Several measures have been initiated to make it a vibrant institution capable of responding to various situations". But as Shrimati Jaya Bachchan pointed out, after nearly 40 years an amendment is being brought; whereas, several measures have been initiated in the past 40 years. Sir, many people have elaborated on natural disaster. They have cited many

instances. Based on those things and experiences of the past, the Government has enacted the Disaster Management Act, 2005. Subsequently, the Disaster Management Act, 2005 has been enacted, inter *alia*, to provide for requisite institutional mechanisms for drawing up and monitoring the implementation of the disaster management plans, ensuring measures by various wings of the Government for prevention and mitigating the effects of disasters and for undertaking a holistic, coordinated and prompt response to any disaster situation. Sir, this Bill serves the basic purpose of natural disaster. This Bill intends to include one clause. It says, "In clause (a) after the words "time of such attack", the words "or any measure taken for the purpose of disaster management, before, during, at, or after any disaster" shall be inserted. It has again been explained that 'disaster' means a disaster as defined in Clause (d) of Section 2 of the Disaster Management Act, 2005. Then 'disaster management' means the disaster management as defined in Clause (e) of Section 2 of the Disaster Management Act, 2005. Sir, while the Disaster Management Act itself has very clearly stated all these things, this has been included in the Civil Defence Act. I can understand the rationale behind it. My only clarification from the hon. Minister is, this amendment tantamount to an impression that powers of the State Government may be infringed upon by the Central Government. All these days, any assistance, from the Central Government, was extended to the State Governments only on the request of the State Governments. Now, this Amendment states that in case of natural disasters, the Central Government may, by itself, extend their assistance to the State Governments, which could infringe upon the rights of the State Governments. I would like to seek a clarification from the hon. Minister on this point, and, I hope, the clarification would allay the apprehensions of the State Governments. With these words, I support the Bill.

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) : सर, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। अभी यहां इस पर बहुत कुछ कहा गया है। मैं एक बात कहना चाहती हूं कि nation के या मनुष्य के character का पता तभी लगता है जब उस पर मुसीबत आती है। जब भी इस देश पर कोई भी मुसीबत आई है, यह देश, यहां की जनता, यहां के लोग हमेशा एक होकर खड़े हुए हैं। चाहे आप 1948 का उदाहरण ले लीजिए, 1962 का ले लीजिए, 1965 का ले लीजिए, "सुनामी" का ले लीजिए या बाढ़ का ले लीजिए, हर समय इस देश ने एक होकर उसका सामना किया है। इसलिए यह कहना कि यहां character नहीं है, मेरे अनुसार गलत है। यहां character है और इसमें nationalism भी है। जब भी इस देश के लोगों के लिए आवाज उठाई गई है, उन्होंने एक होकर काम किया है।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

सर, यह बिल सिविल डिफेंस का है। इसमें मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि हर स्टेट ने अपने अलग-अलग मापदंड बनाए हुए हैं। हमारे यहां हर स्टेट में Home Guards हैं, जो सिविल डिफेंस की सबसे पहली सीढ़ी है,

पहली कड़ी है तथा जिनको हर जगह भेजा जाता है। उनके पास होता क्या है? एक डंडा। डंडा लेकर वे क्या डिफेंस करेंगे, वे क्या मैनेजमेंट करेंगे तथा वे क्या आगे आएंगे! उपसभापति जी, उनके जो wages हैं, वे बहुत कम होते हैं। मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि आप इसमें जो amendments ला रहे हैं, उनके बारे में ठीक ही कहा गया कि इतने सालों बाद लाए। आज जब हमारा पूरा ढांचा बदल गया है, technology बदल गई है, उसमें technical बातें आ गई हैं, equipments change हो गए, तब यह amendments लाना जरूरी था, लेकिन infrastructure का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं यह कहूंगी कि Home Guards, जो हर स्टेट में सिविल डिफेंस की सबसे पहली कड़ी हैं, उनके wages बढ़ाए जाएं तथा उनको equipments दिए जाएं। उनको सिर्फ डंडे देकर ही नहीं खड़ा कर दिया जाए कि आप डंडा लीजिए और disaster management कीजिए। आज मुसीबत के सामने जब उनको आगे किया जाता है तब उनको पहले की तरह ही नहीं रखा जाए, इसलिए यह बहुत जरूरी है। आज से पहले होम गार्डस की ट्रेनिंग होती थी। वह SSB की ट्रेनिंग होती थी और गांव में भी ट्रेनिंग दी जाती थी। महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी और पुरुषों को भी ट्रेनिंग दी जाती थी। मैं तो यही कहूंगी कि जो Girls Guides हैं और Boys Scouts हैं, उनको भी सिविल डिफेंस में involve किया जाए। उन लोगों को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाए। Colleges में जाकर वहां के students को भी बताया जाए, क्योंकि जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है तो विद्यार्थी ही सबसे आगे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन, इसमें उन्हें involve करने के लिए उनको भी बाकायदा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ट्रेनिंग पर ज्यादा emphasize होना चाहिए तथा लोगों को aware करने के लिए ज्यादा emphasize होना चाहिए। इसलिए मैं यह कहूंगी कि इसमें जो changes आप ला रहे हैं, जो amendments ला रहे हैं, उसमें infrastructure और ट्रेनिंग पर ज्यादा ज़ोर दीजिए। पूरे हिन्दुस्तान में, पूरे भारत में, Home Guards एक State subject हैं। इनको स्टेट्स ही रखती हैं तथा वही इनको wages भी देती हैं, लेकिन यहां से इसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि Home Guards के किसी भी cadet को, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, इतनी wages से कम नहीं दी जानी चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... इसी सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहती हूं। यहां भी gender-biased है। Home Guards में जो महिलाएं हैं उनको कम पैसे दिये जाते हैं और जो पुरुष हैं उनको ज्यादा पैसे दिये जाते हैं, जबकि काम उनसे बराबर ही लिया जाता है। इसके बारे में भी सोचा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): Sir, I am highly grateful to the honourable Members who have participated in the discussion on the Civil Defence (Amendment) Bill, 2009, passed by the Lok Sabha, and I sincerely thank them for their valuable suggestions. I am extremely happy that, altogether, seven Members have participated in the discussion and they have all supported this Bill. Once again, I express my sincere thanks to the honourable Members who have actively participated in the discussion on the Bill.

Sir, the concept of Civil Defence had originated during World War II. It was intended to safeguard the life and property of the civilian population. The able-bodied and the able-minded citizens were asked to help protect the common citizens from air raids, etc. during the War. The Civil Defence functioned as an extension of the Army among the common people.

The organisation which spearheaded the Civil Defence during those days was the Air Raid Prevention Organisation. After the conclusion of the Second World War, this organisation was wound up.

In independent India, the idea of involving the civil population in defence mechanism was mooted after the 1962 Chinese aggression and the 1965 Indo-Pak conflict. It was in 1968 that the Civil Defence Act was passed.

Sir, the Civil Defence is intended to be organised primarily on voluntary basis as an integral part of the defence of the country on a limited scale. However, after the 1971 Bangladesh War, the functioning of the Civil Defence became mostly defunct.

The 1968 Civil Defence Act includes any measure, not amounting to actual combat, for affording protection to any person, property, place or thing in India against any hostile attack, be it from air, land, sea or otherwise, whether such measures are taken before, during or after the time of such attack. The Act also aims at providing continued maintenance of Civil Defence services which are already in position in States and Union Territories.

Now, Sir, there are 225 cities and towns in the country which have been categorised as Civil Defence Towns and Cities. Of these 225 towns and cities, 88 have, however, not been activated.

The Civil Defence, at present, is limited to times of external aggression only. Several measures have been initiated for revamping the Civil Defence Organisation to make it a vibrant institution, capable of responding to various situations. In the aftermath of the Kargil War, the need for revamping and strengthening the Civil Defence was emphasised by the Central Government.

The role and the field of responsibility of Civil Defence have been further expanded through Executive instructions for utilising their services for mitigation, prevention and preparedness for disasters as well as for response and relief after a disaster has struck.

Subsequently, Sir, the Disaster Management Act, 2005 has been enacted to provide for requisite institutional mechanism for drawing up and monitoring the implementation of Disaster Management plans.

Further, Sir, as per the National Policy Approach Paper on Civil Defence, it was decided that the Civil Defence Act, 1968 may be amended to cater to the needs of disaster management. The Amendment will help to utilise Civil Defence Volunteers to effectively render their services as part of their duty and enhancement of public participation in Disaster Management related activities.

Sir, India is a country which is prone to natural disasters. In fact, 25 out of 29 States are prone to natural disasters. Sir, 58.6 per cent of our land mass is prone to earthquakes of moderate to very

high intensity. The country has a 7500 kilometres long coastal line, out of which, close to 5700 kms are cyclone-prone and are ravaged every now and then. The mighty rivers flowing through the length and breadth of the country make the country vulnerable to floods. Not only houses and properties are affected, the efforts of many months of hard work by farmers get washed away in these floods. Over 40 million hectares, that is, 12 per cent of the land, are prone to floods and river erosion. Sir, 68 per cent of the cultivable land is vulnerable to drought. Many times, when one part of the country is ravaged by floods, some other part would be reeling under severe drought.

Sir, the Government is responsible to protect the life and property of the people. But the Government machinery by itself may not be able to reach everywhere every time. If there are trained common people present at the site of natural disasters timely help could be better ensured. Trained and motivated civilians can extend a helping hand to the Government and during natural disasters assistance can be reached very fast and losses can be minimised.

Sir, after the passing of the Disaster Management Act, 2005 there is now a paradigm shift in our approach from the post-disaster relief and rehabilitation based 'reactive' approach to the pre-disaster prevention, mitigation and preparedness based 'proactive' approach in a holistic manner.

Sir, the Civil Defence Advisory Committee under the Union Home Minister has recommended implementation of the Scheme for revamping the Civil Defence in the country at an estimated cost of Rs.100 crores during the Eleventh Five Year Plan.

Sir, the Ministry of Home Affairs issued sanction for the above Scheme on 20th April, 2009, which is implemented through Director General of National Disaster Response Force and Civil Defence. The Scheme inter-alia includes upgradation of the existing 17 State Training Institutes in terms of infrastructure, transportation and equipment; establishment of 10 new State Training Institutes; upgradation of facilities in 100 identified Civil Defence Districts. The Scheme also has a pilot project involving an expenditure of Rs.3.25 crores for involving Civil Defence volunteers in assisting the police in law and order and internal security situations.

Sir, the common public who are volunteering to be part of the Civil Defence team can be trained to take action before the onset of a disaster or to identify the signs of natural disasters and warn the public so that life and property losses are minimised. Hence, Sir, it is acutely felt that the Civil Defence can play a very important role in disaster management, and, therefore, it has been proposed to expand the role of Civil Defence by amending the definition of "Civil Defence" as contained in clause (a) of Section 2 of Civil Defence Act 1968, so as to bring within its scope the measures which may be taken for the purpose of disaster management during, at, before or after any disaster. This is the very objective of the Bill, Sir.

Sir, some hon. Members have made some observations and sought certain clarifications on the Bill. One important suggestion which has been made by hon. Member, Shri D. Raja is about the role played by local bodies and panchayats in disaster awareness programmes and all that. Definitely, Sir, we will take this suggestion into serious consideration, and we will try our level best to involve local bodies, including panchayats and gram sabhas, etc., in the awareness programmes on disaster management.

Sir, another question which was posed by hon. Member, Shri Siva is about encroachment of the powers of the State Governments by Central Government. I wish to make it absolutely clear that there is no mala fide intention about interfering in the rights and powers of the State Governments by the Central Government. Not only that, Sir, before finalising the Bill, the State Governments were consulted on this, and all the States had agreed to the amendment. There is absolutely no reason why my dear friend, Shri Siva should express his apprehension in this regard. Sir, I don't think that there are any other important points which have been raised by the hon. Members, in this regard. After passing of this Bill, definitely, the Government of India will take care of the interest of the people, and we will try our level best to protect the property and life of the people of this country. So, I request the hon. Members to support this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Civil Defence Act, 1968, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, we shall now take up the Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2009. A decision has already been taken to pass this Bill without any discussion. ...*(Interruptions)*...

The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2009

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI AJAY MAKEN): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI AJAY MAKEN: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

Motion for reference of the Bill to a select Committee the Commercial Division of High Courts Bill, 2009.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Sir, I move the following motion:-

"That the Bill, to provide for the constitution of a Commercial Division in the High Courts for adjudicating commercial disputes and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following Members:-

1. Shri Shantaram Laxman Naik
2. Shrimati Jayanthi Natarajan
3. Prof. P.J. Kurien
4. Shri Santosh Bagrodia
5. Shri M. Rama Jois
6. Shri Balavant *alias* Bal Apte
7. Dr. V. Maitreyan
8. Shri P. Rajeeve
9. Shri Virendra Bhatia
10. Shri Satish Chandra Misra
11. Shri Tiruchi Siva
12. Shri D. Raja

with instruction to report to the Rajya Sabha by six weeks."

The question was put and the motion was adopted.